

स्वतंत्र प्रभात



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia	@swatantramedia	RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)	@SwatantraPrabhatonline	news@swatantraprabhat.com
सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून			सीतापुर, मंगलवार, 05 मई 2026	
सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे 2 बच्चों को एयरफॉर्स हेलिकॉप्टर से सेना ने किया रेस्क्यू...03			वर्ष 14, अंक 26, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया www.swatantraprabhat.com	
			गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित	
			ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने टुकराया...04	

बंगाल में बदला नहीं, बदलाव की बात हो विधानसभा

चुनावों में जीत के बाद बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार शाम को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया. इस अवसर पर पूरा परिवार मोदी-मोदी के नारे से गूंज उठ. पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भारत माता के नारे के साथ की. पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है. बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन भाजपा कार्यालय पहुंच गये हैं. उनका भाजपा मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया. भाजपा मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को समझ नहीं पाई है. बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है. हमारे लिए भारत सब कुछ है. भारतीयता सबकुछ है. पीएम मोदी ने कहा कि महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को धुल नहीं जाएगी. आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो. एक भी नहीं है. ये सिर्फ सिंघासत का बदलाव नहीं है. सोच का बदलाव है. यह बदलाव है कि विकसित होता भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है. आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है और विकास चाहता है. प्रति और स्थिरता चाहता है. आज का भारत, ऐसी राजनीति चाहता है, जो देश को आगे बढ़ाए, लेकिन दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़े है. ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है. कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है, जिससे देश में टुकड़ा दिया है. जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है. कांग्रेस में जड़े मजबूत कर रहा है. कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का पिछे बनते जा रही है. पीएम मोदी ने कहा कि अंग, बंग और कलिंग को मजबूत होना बहुत जरूरी है. गर्व है कि हमने एनडीए को चुन लिया है. नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे

बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने रोकने का काम किया है. संसद में नारी शक्ति वंदन संरोधन विधेयक को पास नहीं होने नहीं दिया. इसलिए मैंने पहले कुछ दिन पहले कहा था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा. कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों-बेटियों ने सजा दी है. पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में अब बदला नहीं, बदलाव की बात हो. सभी दल हिंसा के चक्र को खत्म करें. पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बंगाल में पहली बार शांतिपूर्ण चुनाव हुआ. एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई. बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है. आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है. विकास के भरोसे से युक्त हुआ है. बांगलाय परिवर्तन होए गए. पीएम मोदी ने कहा कि पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को ही इंजी दिखाई जाएगी. घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. पीएम मोदी ने कहा कि केरल और बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कितने जुल्म हुए हैं कितने अत्याचार हुए हैं. आज बंगाल में भाजपा की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को देता हूं, मैं जीत की जनता बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं. चार मई की शाम भले ही चल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर एक नया सूर्योदय हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद की आत्मा को शांति मिली है. उन्होंने जिस बंगाल का सपना देखा था. आज चार मई, 2026 को बंगाल की जनता हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है. बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है. आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है. विकास के भरोसे से युक्त हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना, अपने आप में ऐतिहासिक रहा है. असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे



महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है. ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है. पीएम मोदी ने कहा कि आज 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए-भाजपा की सरकार है. हम नागरिकों की सेवा में जुटे हैं. इसलिए जनता का भरोसा है. जनता साफ देख रही है. जनता साफ देख रही है. जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में जीत मिली. यह सफलता केवल राज्यों के चुनावों में नहीं दिखाई जाएगी. घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. पीएम मोदी ने कहा कि केरल और बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कितने जुल्म हुए हैं कितने अत्याचार हुए हैं. आज बंगाल में भाजपा की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को देता हूं, मैं जीत की जनता बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं. चार मई की शाम भले ही चल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर एक नया सूर्योदय हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद की आत्मा को शांति मिली है. उन्होंने जिस बंगाल का सपना देखा था. आज चार मई, 2026 को बंगाल की जनता हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है. बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है. आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है. विकास के भरोसे से युक्त हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना, अपने आप में ऐतिहासिक रहा है. असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे

ने कहा कि जब वर्षों की साधना, सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं. पीएम मोदी ने कहा कि भरोसा भारत के लोकतंत्र पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना पर है. नितिन नबीन ने कहा कि इस चुनाव के बाद इंजी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा. नारी वंदन विधेयक को खारिज करने पर जनता ने सबक सिखाने का काम किया है. नितिन नबीन ने कहा कि आज पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारी देवतुल्य जनता ने हमें जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं इन सभी पांच राज्यों के लोगों का अभिन्दन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति और भाजपा-NDA के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है. नितिन नबीन ने कहा कि यह जीत काफी संघर्ष के बाद मिली है. बंगाल में पूरा भय का वातावरण बना हुआ था. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि आज की प्रचंड जीत ने 2024 के कसक को पूरा किया है. पीएम मोदी ने प्रति आस्था जताया है. पीएम मोदी ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को माला पहनाकर लिए निरंतर काम करती रहेगी. पुदुचेरी के हर परिवार की समृद्धि यही हमारा संकल्प है. पीएम मोदी ने कहा कि मां गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र का भी आशीर्वाद रहा है. असम में तीसरी बार भाजपा पर जनता ने भरोसा किया है. ये असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है. असम अपने विकास की रफ्तार और बढ़ाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल-कमल ही खिलती है. मां गंगा के किनारे के राज्यों में अब बीजेपी-एनडीए की सरकार है. पीएम मोदी ने कहा कि जय और परजय लोकतंत्र और चुनावी भयमुक्त हुआ है. विकास के भरोसे से युक्त हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना, अपने आप में ऐतिहासिक रहा है. असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे

रणनीति, संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट... बंगाल में

बीजेपी की जीत की शाह ने ऐसे लिखी कहानी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव की इस कहानी के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, संगठन क्षमता और जमीनी पकड़ को निर्णायक कारक माना जा रहा है. करीब पंद्रह दिनों तक लगातार बंगाल में डेरा डालकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ आक्रामक चुनावी अभियान चलाया, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में पूरे मिशन को अंतिम चरण तक सटीक तरीके से संचालित किया. दिन में रैलियों और रोड शो के जरिए उन्होंने माहौल तैयार किया, तो रात में संगठन को धार देने का काम किया. देर रात तक चलने वाली बैठकों में अमित शाह लगातार जमीनी फीडबैक लेते, स्थानीय नेताओं को दिशा देते, रणनीति तय करते और अगले ही दिन उसे जमीन पर लागू कराते. पचास से अधिक रैलियों और रोड शो के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया और मतदाताओं तक सीधे संवाद स्थापित किया. चुनाव के दौरान की गई उनकी प्रमुख घोषणाएं—जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा और कानून-व्यवस्था पर सख्ती ने मतदाताओं के बीच स्पष्ट और ठोस राजनीतिक संदेश दिया.



मतदाताओं के बीच सत्ता परिवर्तन की संभावना की धारणा बनी, जिसने चुनावी रणनीति को प्रभावित किया. हालांकि, यह सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की रणनीति का परिणाम नहीं थी. अमित शाह के साथ पांच प्रमुख नेताओं की टीम ने संगठित और समन्वित तरीके से हर मोर्चे पर काम किया. भूपेंद्र यादव ने संगठन के माइक्रो-और मतदाताओं तक सीधे संवाद स्थापित किया. चुनाव के दौरान की गई उनकी प्रमुख घोषणाएं—जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा और कानून-व्यवस्था पर सख्ती ने मतदाताओं के बीच स्पष्ट और ठोस राजनीतिक संदेश दिया.

शाह की टीम ने बंगाल में किया कमाल

पहले चरण के मतदान के बाद उनका यह दावा कि बीजेपी 110 से अधिक सीटें जीत रही है, मनोवैज्ञानिक बड़बूत साबित हुआ. इससे दूसरे चरण में

माइक्रो-मैनेजमेंट से पलटा खेल सुनील बंसल ने संगठन को नई धार दी. पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए उन्होंने ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा किया, जिसने टीएमसी के कैडर-आधारित ढांचे को सीधी चुनौती दी. उन्होंने नेताओं के बीच तालमेल बैठाने के साथ-साथ पिछले चार

साक्षिप्त खबरें

असम में NDA की शानदार जीत, सरकार के काम और विकास के एजेंडे पर जनता ने लगाई मुहर : हिमंत



असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधानसभा चुनाव में राजन के शानदार प्रदर्शन के लिए जनता का आभार जताते हुए सोमवार को कहा कि यह परिणाम सरकार के अच्छे काम और राज्य के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर का प्रतिबिंब है। शर्मा ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'यह सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राज्य) के लिए अभूतपूर्व जीत है। यह पहला मौका है जब भाजपा ने राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम विधानसभा चुनाव के अब तक घोषित नतीजों में भाजपा 62 सीटें जीत चुकी है और 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि उसकी सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) को सात सीटें मिलीं और तीन पर बढ़त है। राजन के अन्य सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) चार सीट जीत चुकी है और छह सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर शर्मा ने कहा, 'लोगों ने गायक जुबीन गर्ग की मौत का राजनीतिकरण करने के लिए उन्हें सजा दी है।' मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक-दो को छोड़कर विपक्ष में कोई हिंदू विधायक नहीं होगा और राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने और 'बांग्लादेशी मियाओं' की 'आक्रामकता' से लड़ने के लिए 'अच्छे' हिंदू कांग्रेसी नेताओं से भाजपा में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'हैट्टिक के साथ शतक!', क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन तीन अंकों के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है।'

ढेर हुए धुरंधर, चमक उठी 2 साल पुरानी पार्टी... तमिलनाडु

के रण में कैसे हुई एक्टर विजय की पार्टी की जय-जय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महज दो साल पुरानी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की 50 साल से ज्यादा समय से चली आ रही दो धुनों में बंदी राजनीति को हिला कर रख दिया. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को हुई मतगणना में अभिनेता से नेता बने विजय ने 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रखी है. नतीजे बताते हैं कि फिल्म सुपरस्टार विजय अपनी सिनेमाई लोकप्रियता को वोटों में बदलने में कामयाब रहे. नतीजा विजय की अर्न स्क्रीन लोकप्रिय तमिलनाडु में राजनीतिक ताकत के रूप में जनता के सामने है. तमिलनाडु की जनता राजनीति के द्रविड़ मॉडल से ऊब गई थी. राज्य में बारी बारी से कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके की सरकारें तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती थी. उनको विजय में उम्मीद और विकल्प दिखा. खासकर राज्य के युवाओं और महिला वोटों में विजय का जबरदस्त क्रेज था. फिल्मों की तरह असल जावन में भी विजय ने युवाओं को एक शांत पर फुलेन पड़ुकर राजनीतिक ढांचे को तोड़ने वाले हीरो के रूप में नजर आए.

सिनेमाई करिश्मा बना चुनावी ताकत

विजय ने अपना प्रोजेक्शन एक ऐसे नेता के तौर पर किया जो द्रविड़ आईडेंटिटी का सम्मान तो करता है पर जाति और धर्म के नाम पर धुन्नीकरण

के खिलाफ है. विजय ने राज्य के दलित और अल्पसंख्यक वोटों के एक बड़े हिस्से को भी अपनी तरफ खींचा. लेकिन विजय के लिए यह जनी आसान नहीं रही. पिछले साल सितंबर में विजय की कस्टर रैली में 41 लोगों की मौत के बाद से अब सत्ता की दहलीज तक का सफर को हुई मतगणना में अभिनेता से नेता बने विजय ने 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रखी है. नतीजे बताते हैं कि फिल्म सुपरस्टार विजय अपनी सिनेमाई लोकप्रियता को वोटों में बदलने में कामयाब रहे. नतीजा विजय की अर्न स्क्रीन लोकप्रिय तमिलनाडु में राजनीतिक ताकत के रूप में जनता के सामने है. तमिलनाडु की जनता राजनीति के द्रविड़ मॉडल से ऊब गई थी. राज्य में बारी बारी से कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके की सरकारें तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती थी. उनको विजय में उम्मीद और विकल्प दिखा. खासकर राज्य के युवाओं और महिला वोटों में विजय का जबरदस्त क्रेज था. फिल्मों की तरह असल जावन में भी विजय ने युवाओं को एक शांत पर फुलेन पड़ुकर राजनीतिक ढांचे को तोड़ने वाले हीरो के रूप में नजर आए.

DMK-AIADMK के एकाधिकार को चुनौती

तमिलनाडु में एक्ट विजय को सत्ता के नजदीक पहुंचाने में मौजूद डीएमके सरकार की सत्ता विरोधी लहर ने भी मदद की. डीएमके की परिवारवाद की युवाओं को एक शांत पर फुलेन पड़ुकर राजनीतिक ढांचे को तोड़ने वाले हीरो के रूप में नजर आए.

बंगाल-असम में बीजेपी की बढ़त पर जश्न: CM

Yogi ने मंत्रियों संग मनाई जीत की खुशी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटों के लिए हो रही मतगणना के लिए कुल 292 रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दोपहर ढाई बजे तक 193 सीटों पर बढ़त बनाई हुयी है जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को केवल 94 सीटों पर ही बढ़त हासिल हुयी है। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है। असम विधानसभा चुनाव 2026 और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में भाजपा की बढ़त के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक से पहले प्रदेश कैबिनेट



सागर (पश्चिम बंगाल) तक कमल खिल गया है... प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण हमें पश्चिम बंगाल में जीत मिली, असम में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और पुदुचेरी में भी दूसरी बार हमारी सरकार बन रही है। हमें पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु, केरल में भी कमल खिलेगा। इस वक्त भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता, समर्थक खुशी से झूम रहा है। अखिलेश यादव बहुत कहते थे कि दीदी जीतोगी, भाजपा हागेगी... लेकिन आम आदमी पार्टी, RJJD और TMC का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया और अरब सागर (महाराष्ट्र) से लेकर गंगा

विजय के साथ हो लिए. उधर AIADMK भी नेतृत्व की लड़ई से बिखरता चला गया. ईपीएस और ओपीएस की गुलबजी और फुलेने नेताओं के साथ छोड़ने के चलते जनता और दृष्ट्यक्ष कार्यकर्ताओं को पार्टी को लेकर भरोसे का संकट दिखा. असर ये हुआ कि एआईडीएमके के भरोसेमंद वोटर जो डीएमके के साथ नहीं जा सकते थे. उन्होंने भी एक्टर विजय की पार्टी में अपना नया ठिकाना ढूँढा.

फैन क्लब, युवा और महिला वोटों की भूमिका

विजय के शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर वादों ने पहुंचे लिखे माध्यम वर्ग को उम्मीद दी, जो डीएमके और एआईडीएमके के प्रो वादों के कस्टर से पेशान थे. विजय ने पूरे चुनाव में कोई इंस्ट्रुक्श नहीं दिया, जिससे अनावश्यक विवाद और आंगण-प्रत्यारोप की लड़ई से बचे रहे. विजय की पार्टी का छेपे छेपे गानों, वीडियो संदेश का सोशल मीडिया और डिजिटल कैमन का तरीका भी शहरी और ग्रामीण वोटरों को खूब भाया. जानकार बताते हैं कि न्यूट्रल और पोलिटिंग वोटरों ने भी काफी हद तक विजय को वोट किया. भाषाई विवाद और रीजनल पहचान के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ डीएमके को वोट करने वाले वोटरों ने भी विजय को ही विकल्प के तौर पर देखा.

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्रा की रैगिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो में पीड़ित छात्रा के बाल खींचे जा रहे हैं, उसे थपड़ मारे जा रहे हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है. छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल है. वहीं संस्थान की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. हालांकि, घटना को लेकर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला रैगिंग का है या फिर छात्राओं के बीच किसी व्यक्तिगत विवाद का नतीजा है. वीडियो में दिखाई दे रही हिंसा और बदसलूकी ने मामले को काफी गंभीर बना दिया है. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी इस घटना को हल्के में नहीं लिया है.



वीडियो की जांच के लिए समिति का गठन

तत्काल प्रभाव से वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके. यूनिवर्सिटी प्रबंधन मुताबिक, इस पूरे मामले में एक जांच समिति बनाई गई है, जो इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है. साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो की सत्यता, घटना का समय-स्थान और इसमें शामिल छात्रों के पहचान जैसे सभी पहलुओं को बारीकी से जांच करें. इसके लिए पांच दिनों की समय अवधि निर्धारित की गई

जुलिस को नहीं मिली शिकायत

पांच रिपोर्ट के आधार पर तय किया

शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की बढ़त देख बोले शशि

थरूर- अब प्राथमिकता केरल का सुधार करना है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और यूडीएफ (UDF) के शानदार प्रदर्शन के बीच वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राज्य की भविष्य की दिशा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार सुबह जारी मतगणना में कांग्रेस नीत गठबंधन को बढ़त मिलता देख थरूर ने कहा कि अब समय आ गया है कि केरल में सरकार और नीतियों, दोनों में बदलाव कर राज्य का सुधार किया जाए।



केरल को 'इन्वेस्टमेंट हब' बनाने पर दिया जोर

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शशि थरूर ने राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार बदले और नीतियां बदले ताकि केरल का विकास फिर से पटरी पर आ सके। थरूर ने कहा कि वे केरल को निवेश के लिए एक सुरक्षित ठिकाना

जाएगा कि मामला वास्तव में रैगिंग का है या नहीं और इसमें शामिल छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सतर्क है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. एसीपी दादरी प्रशाली गंगवार के अनुसार, वायरल वीडियो लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि अब तक न तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से शिकायत आ ही पीड़ित छात्रा की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई है. ऐसे में पुलिस फिलहाल जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. उनका यह भी कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो शिकायत के आधार जांच के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जुलिस को नहीं मिली शिकायत पांच रिपोर्ट के आधार पर तय किया

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता की वैश्विक चुनौतिया

अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और यह दिन लोकतंत्र की उस मूल भावना को उजागर करता है, जिसमें 330 नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस 1991 के विंडहोक घोषणा पत्र से प्रेरित है, जिसने स्वतंत्र और बहुलतावादी मीडिया की आवश्यकता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। आज जब हम 2026 के वैश्विक परिटूरूप पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और डराने वाली प्रतीत होती है। वैश्विक सूचकांक के आंकड़े इस बात की तस्वीर करते हैं कि दुनिया के 180 देशों में से आधे से अधिक देशों में प्रेस की स्थिति या तो बहुत कठिन है या फिर बेहद गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। यह जानकर हृदय कांप उठता है कि विश्व की 1 प्रतिशत से भी कम आबादी आज उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहाँ प्रेस को वास्तव में स्वतंत्र और सुरक्षित माना जा सकता है। पिछले 25 वर्षों का इतिहास गवाह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर दबाव निरंतर बढ़ा है और पत्रकारों के काम करने की गुंजाइश संकुचित हुई है। पत्रकारिता आज एक ऐसा पेशा बन गया है जहाँ सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 129 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई, जो अब तक का सबसे बड़ा और विचलित करने वाला आंकड़ा है। यह संख्या केवल एक डेटा नहीं है, बल्कि उन आवाजों की खामोशी है जो समाज की विसंगतियों पर प्रहार कर रही थीं। सन 2000 से लेकर अब तक लगभग 1795 पत्रकारों ने अपने कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्यौछार किए हैं, जो इस पेशे के बड़े जोखिमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

हिंसा के साथ-साथ कानूनी उर्पीड़न भी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर की जेलों में लगभग 330 पत्रकार बंद हैं, जिनमें से 61 प्रतिशत पत्रकारों पर राष्ट्रविरोधी होने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे संगीन आरोप मढ़े गए हैं। विडम्बना यह है कि जिन कानूनों का निर्माण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया था, उनका उपयोग अक्सर उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जो सत्ता की खामियों को उजागर करने का साहस करते हैं। पत्रकारिता को अपराध की तरह देखे जाने की यह प्रवृत्ति किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। इससे भी अधिक चिंता का विषय वह न्यायहीनता है जो पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में व्याप्त है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों की हत्या के लगभग 86 प्रतिशत मामलों में अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलती। यह न्याय की विफलता न केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है बल्कि क्षेत्र में कार्यरत अन्य पत्रकारों के मन में भी भय का संचार करती है। जब सच के पहरेदारों को लगने लगता है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और उनके हत्यारे खुलेआम घूम सकते हैं, तो वे आत्म-संसेरशिप का रास्ता चुनने को मजबूर हो जाते हैं, जो अंततः लोकतंत्र की मृत्यु की शुरुआत होती है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर केवल भौतिक हमला ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि आज के दौर में इसके स्वरूप बदल गए हैं। कई देशों में मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग एक सुनियोजित हथियार की तरह किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक दबावों के जरिए मीडिया संस्थानों की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन और वित्तीय संसाधनों के वितरण में पक्षपात करके उन संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है जो सत्ता के सुर में सुर मिलते हैं, जबकि आलोचनात्मक रुख अपनाते



वाले संस्थानों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाता है। इस बदलती दुनिया में डिजिटल युग ने जहाँ सूचना के प्रसार को पंख दिए हैं, वहीं पत्रकारों के लिए नई और जटिल चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार और गलत जानकारियों का जाल इतनी तेजी से फैलता है कि तथ्य और झूठ के बीच का अंतर मिटने लगता है। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर हमले और अवैध डिजिटल निगरानी ने पत्रकारों के निजी और पेशेवर जीवन को असुरक्षित बना दिया है। विशेष रूप से महिला पत्रकारों को ऑनलाइन को लगने लगता है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और उनके हत्यारे खुलेआम घूम सकते हैं, तो वे आत्म-संसेरशिप का रास्ता चुनने को मजबूर हो जाते हैं, जो अंततः लोकतंत्र की मृत्यु की शुरुआत होती है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर केवल भौतिक हमला ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि आज के दौर में इसके स्वरूप बदल गए हैं। कई देशों में मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग एक सुनियोजित हथियार की तरह किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक दबावों के जरिए मीडिया संस्थानों की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन और वित्तीय संसाधनों के वितरण में पक्षपात करके उन संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है जो सत्ता के सुर में सुर मिलते हैं, जबकि आलोचनात्मक रुख अपनाते

दरअसल लोकतंत्र का वह दर्पण है जिसमें समाज अपनी असलियत देखता है। यदि इस दर्पण पर धूल जमा दी जाए या इसे थुंधला कर दिया जाए, तो समाज अपनी कमजोरियों को कभी सुधार नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमें यह अक्सर प्रदान करता है कि हम उन साहसी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर सच की मशाल को जलाए रखा। यह दिन सरकारी के लिए भी एक चेतावनी है कि वे प्रेस की आजादी के प्रति अपनी सवैधानिक और नैतिक प्रतिबद्धताओं को फिर से परिभाषित करें। यह आवश्यक है कि ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और न्याय प्रणाली को इतना मजबूत बनाया जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून की पकड़ से बाहर न रहे।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना किसी एक समूह का दायित्व नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि यदि आज हम पत्रकारों की आवाज दबाने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो भविष्य में हमारी अपनी आजादी भी छीन ली जाएगी। लोकतंत्र की जीवन्तता के लिए यह अनिवार्य है कि प्रेस बिना किसी डर या प्रलोभन के अपना कार्य कर सके। जब तक दुनिया में एक भी पत्रकार को सच बोलने के लिए जेल भेजा जाएगा या उसकी हत्या की जाएगी, जब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। प्रेस की आजादी की मशाल को प्रज्वलित रखना ही इस दिवस की सार्थकता है, ताकि आने वाली दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक में गिरावट देखी माँद है। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक संस्थानों के भीतर असहमति के स्वयं के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है। प्रेस की स्वतंत्रता

महेन्द्र तिवारी

(मेक इन इंडिया) स्वावलंबन एवं स्व-रोजगार बेहतर विकल्प

[युवा ऊर्जा से राष्ट्र का विकास संभव।]

आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थान में लड्डू प्रसाद के लिए धी खरीद में सामने आया कथित घोटाला केवल एक प्रशासनिक अनियमितता का मामला नहीं है बल्कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता और सार्वजनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता बल्कि वह विश्वास, परंपरा और भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र होता है। ऐसे में जब प्रसाद जैसी पवित्र मानी जाने वाली वस्तु में मिलावट की आशंका सामने आती है तो उसका असर सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह आस्था की नींव को भी हिला देता है। जांच समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि लगभग सत्तर लाख किलोग्राम धी बिना अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षण के खरीदा गया और कई मामलों में लैब रिपोर्ट आने से पहले ही उसका उपयोग प्रसाद बनाने में कर लिया गया। यह स्थिति किसी एक स्तर की चूक नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है जिसमें निधियों की अनदेखी, निगरानी की कमी और संधावित मिलीभगत शामिल हो सकती है। जब किसी धार्मिक संस्था में इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री का उपयोग हो रहा हो तो उसके हर चरण पर सख्त नियंत्रण और पारदर्शिता अपेक्षित होती है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अगस्त 2022 की लैब जांच में सैंपलों में सिटोस्टेरॉल की मौजूदगी पाई गई जो वनस्पति तेल की मिलावट का संकेत माना जाता है। इसके बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई और सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करने जैसे कदम नहीं उठाए गए। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब मिलावट के संकेत स्पष्ट थे तो जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए। इससे यह संदेह गहरता है कि कहीं न कहीं प्रणाली में गंभीर खामियाँ या जानबूझकर की गई लापरवाही मौजूद थी।

खरीद प्रक्रिया में भी कई ऐसी बातें सामने आईं जो चिंता बढ़ाती हैं। असामान्य रूप से कम बोली स्वीकार करना,



नीलामी के बाद अनौपचारिक बातचीत के जरिए कीमत कम करने की अनुमति देना और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करना यह दर्शाता है कि आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी गई जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। शुद्ध धी की कीमत और बाजार की वास्तविकता को देखते हुए अत्यधिक कम कीमत पर सप्लाई होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। इस पूरे मामले में एक संगठित नेटवर्क के काम करने की आशंका भी जताई गई है जिसमें सप्लायर, बिचौलिये और कुछ संस्थागत तत्व शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख सप्लायर ने वनस्पति तेल और अन्य एडिटिव्स का उपयोग कर मिलावट की तैयारी किया और अयोग्य घोषित होने के बाद भी वह अन्य माध्यमों से सप्लाई जारी रखने में सफल रहा। यह स्थिति दर्शाती है कि निगरानी प्रणाली में गंभीर कमजोरियाँ थीं और नियमों को लागू करने में इच्छाशक्ति की कमी थी। पूर्व अधिकारियों और खरीद समिति की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि टेंडर नियमों को कमजोर किया गया और मिलावट की पुष्टि के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हालाँकि संबंधित पक्षों का कहना है कि सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए और नियमों के तहत ही प्रक्रिया अपनाई गई। यह विवाद

को सही ढंग से लागू किया जाए तो मिलावट जैसी समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

स्वकार और संबन्धित संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि वे इस मामले को केवल एक आरोप या राजनीतिक विवाद के रूप में न देखें बल्कि इसे एक सुधार के अवसर के रूप में लें। यदि जांच में दोष सिद्ध होते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, गुणवत्ता परीक्षण को अनिवार्य और समयबद्ध करने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

श्रद्धालुओं के दुष्टिकों से यह घटना बेहद संवेदनशील है। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक होता है। लोग इसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। ऐसे में यदि उसमें मिलावट की बात सामने आती है तो यह विश्वास को गहरा आघात पहुंचाती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे पुनः स्थापित करना बेहद कठिन होता है।

इस पूरे प्रकरण से एक महत्वपूर्ण सीख यह मिलती है कि धार्मिक संस्थानों में भी पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का समावेश आवश्यक है। केवल परंपरा के आधार पर व्यवस्था को चलाना अब पर्याप्त नहीं है। बदलते समय के साथ संस्थानों को भी अपने कामकाज में सुधार लाना होगा ताकि वे श्रद्धालुओं के विश्वास पर खरे उतर सकें। यह मामला केवल धी की गुणवत्ता या खरीद प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न से जुड़ा है कि क्या हम अपनी आस्था से जुड़े संस्थानों में भी उतनी ही सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित कर पा रहे हैं जितनी अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अपेक्षित होती है। यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो यह समय है। कि हम इससे सीख लें और आवश्यक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाएँ ताकि भविष्य में आस्था और विश्वास दोनों सुरक्षित रह सकें।

संजीव तारु

लड्डू प्रसाद में मिलावट का सच: आस्था, व्यवस्था और जवाबदेही पर गहरा सवाल

स्वयं की क्षमता, शक्ति एवं ऊर्जा को पहचानना आज के नव युवकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वयं के विकास से तात्पर्य खुद के लिए अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार रोजगार की तलाश राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। भारत की विशाल आबादी के हिसाब से भारत नौजवानों का देश है और भारत सरकार के लिए इतने युवा लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना संभव भी नहीं है कि सभी युवकों के लिए समुचित नौकरी का प्रबंध या इंतजाम कर सके। ऐसे में पहले-पहले नौजवानों का यह महती दायित्व बन जाता है कि वह स्वयं की क्षमता को पहचान कर मेक इन इंडिया या स्वावलंबी होने का भरसक प्रयास करें। स्वयं की क्षमता को पहचानने वाला व्यक्ति समाज में एक आदर्श बनकर उभरता है और उसकी प्रसिद्धि समाज में स्वयं हो जाती है। युवक स्वयं का रोजगार बनाकर न सिर्फ खुद की बेरोजगारी दूर करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी रोजगार का साधन बन जाता है। यह राष्ट्रीय हित में अत्यंत आवश्यक समीचीन तथा राष्ट्रीय विकास के लिए एक अच्छे सूचक के रूप में सामने आता है। स्वयं अपनी क्षमताओं को पहचानना एवं अपने अंदर के उद्यमी को रोजगार के लिए उपयोग में लाना मनुष्य के एक तरह का अलंकार या आभूषण ही है जो मनुष्य के लिए सुखी होने का बड़ा स्रोत है। वैसे भी नौकरी

करके युवा एक तरह से परतंत्र, पराधीन हो जाता है और अपनी क्षमताओं का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाता यही कारण है कि राष्ट्र के समग्र विकास में उसकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय योजना मेक इन इंडिया के अंतर्गत आव्हान किया गया है कि नौजवानों को अपनी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं स्किल का उपयोग कर भारत देश के लिए हर तरह के आवश्यक वस्तुओं का स्वयं निर्माण करें एवं दूसरे नौजवानों के लिए आदर्श स्थापित करें जिससे संपूर्ण देश स्वावलंबी लिखे नौजवानों का यह महती दायित्व बन जाता है कि वह स्वयं की क्षमता को पहचानने वाला व्यक्ति स्वतंत्र, स्वाभिमानी होकर स्वयं पर पूर्ण विश्वास करने वाला आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है। ऐसे में भविष्य में राहों में जितनी भी मुश्किल है या कठिनाई आती है उसका वह अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने से नहीं चूकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानने के कारण व्यक्ति अत्यंत सरल, सहज एवं आत्मविश्वासी होकर दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता। स्वयं का रोजगार तलाशने या अपने लिए कोई उद्यम बनाने में युवाओं में जो ज्ञान है। प्रसाद होता है फल स्वरूप वह युवा अत्यंत त्यागी तथा समाज के लिए सेवा भाव भी रखने वाला होता है। स्वावलंबन से दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती एवं अपने ही ज्ञान तथा क्षमता से वह उन्नति के



सोपान चढ़ते जाता है, एवं राष्ट्र के लिए एक धरोहर की तरह होता है। खुद की क्षमता पहचान कर अपना उद्यम डालने से न सिर्फ समाज में विकास होता बल्कि देश में भी विकास के योगदान में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होता है।

ऐतिहासिक तौर पर भी खुद की क्षमता पहचानने एवं अपनी उर्जा को सही दिशा में लगाने के कारण बड़े-बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, वे पैदाइशी महापुरुष नहीं थे उन्होंने अपनी क्षमता, शक्ति एवं ज्ञान को पहचान कर उसमें समुचित एवं निरंतर परिश्रम कर एक नए मुकाम को हासिल किया था और तब ही वे महापुरुषों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। परिणामिक तौर पर प्रभु श्री

न्यायपालिका में बढ़ता मुकदमों का बोझ: न्याय में देरी, अन्याय से कम नहीं

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, लेकिन आज यह खुद भारी बोझ तले दबी हुई है। मुकदमों का अंबर लगा है और लोगों को तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इसे पटरी पर नहीं लाया जा सके लेकिन बिना प्रयास किए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कई कारण हैं जिनको यदि ठीक कर दिया जाए तो व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को न्याय मिलने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। विचाराधीन आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 तक, भारत की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। इनमें से 70% से अधिक केस जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं।



इस्तेमाल करते हैं। एक गवाह के बयान में ही कई-कई तारीख लग जाती हैं। निचली अदालतों में सजा की दर कम है, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलों का बोझ बढ़ता जाता है। सही मायने में न्याय में देरी भी अन्याय से कम नहीं है। जब पीड़ित को 20 साल बाद इंसाफ मिले तो उसका क्या मतलब ही क्या रह जाता है। हमारी जेलें भी भरी हुई हैं उसका मुख्य कारण है कि जेलों में 75% से ज्यादा कैदी अंडरट्रयाल हैं। यानी दोषी साबित होने से पहले ही सालों जेल कारा रहे हैं। मुकदमों में फंसे होने से व्यापार, निवेश और प्रोजेक्ट रुकते हैं। जब सिस्टम से उम्मीद टूटती है तो लोग कोर्ट से बाहर समझौता या दबाई का सहारा लेते हैं।

यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 जज हैं। जबकि लॉ कमीशन की 1987 की सिफारिश 50 जज प्रति 10 लाख की थी। विकसित देशों में यह आंकड़ा 50-150 तक है। जजों की संख्या आधी से भी कम है, और यही कारण है कि हमें न्याय मिलने में देरी पर देरी होती रहती है। इसलिए हमें इसके समाधान का राह ढूँढनी और विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक सिविल केस निपटाने में औसतन 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं। कई फौजदारी केस 15-20 साल तक खिंचते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 34 स्वीकृत पदों में से छहटा 2-4 खाली रहते हैं। हाई कोर्ट में 25% और जिला अदालतों में 20% से ज्यादा पद खाली हैं। भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है। कई पीठियाँ एक ऐसे समाज में सांस ले सकें जहाँ सूचना पर किसी का एकाधिकार न हो और सच बोलने का साहस करने वालों को सम्मान मिले, न कि सजा।

महेन्द्र तिवारी

बढ़ती महंगाई से बेहाल आम जनजीवन को राहत की आस

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभाव से आज पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है और भारत भी इससे अछूटा नहीं है। अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है, जिसका सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत, जो अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, स्वाभाविक रूप से इस संकट से प्रभावित हुआ है। भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि देश की बड़ी आबादी आज भी सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों पर निर्भर है। ऐसे में महंगाई का सीधा असर आम आदमी, विशेषकर मध्यम और गरीब वर्ग के जीवन पर पड़ता है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक सब कुछ महंगा हो जाता है। खाड़ी क्षेत्र, जहाँ से विश्व के अधिकांश देशों में तेल और गैस की आपूर्ति होती है, लंबे समय से भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में, खासकर होमुजुंजलदमध्यम से तेल आपूर्ति में बाधा की आशंका ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यदि यह संकट लंबा खिंचता है, तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और महंगाई, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। हाल ही में भारत में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों और छोटे (5 किलोग्राम) गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। होटल, ढाबा और छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों के लिए यह अतिरिक्त बोझ है, जिसे वे संतप्त उभानेवालों पर डालने को मजबूर होंगे। इसका असर उन लाखों छात्रों और श्रमिकों पर पड़ेगा, जो अंततः अपने भोजन और सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन करते हैं। यह सही है कि वैश्विक कारणों से उत्पन्न महंगाई को पूरी तरह नियंत्रित करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब देश की बड़ी आबादी सामाजिक सुस्था योजनाओं पर निर्भर है। इसके बावजूद सरकार ने अब तक आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने और महंगाई के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास किए हैं, जो सख्तनीय हैं। हालाँकि, राजनीतिक परिदृश्य में अक्सर महंगाई जैसे मुद्दों का उपयोग आरोप-प्रत्यारोप के लिए किया जाता है। इससे न केवल जनता भ्रमित होती है, बल्कि वास्तविक समाधान पर ध्यान भी कम हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी पक्ष मिलकर रचनात्मक सुझाव दें और देशहित में काम करें। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को संतुलित नीति अपनानी होगी। आवश्यक वस्तुओं—जैसे खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए—रहत आया किए जा सकते हैं, वहीं विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़कर राजस्व संतुलन बनाया जा सकता है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और आर्थिक संतुलन भी बना रहेगा। अंततः हमें देखा गया है कि महंगाई, विशेषकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, सरकारों के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार समय रहते प्रभावी कदम उठाए, ताकि बढ़ती महंगाई से जूझ रहे आम, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। अंततः, देश की जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके जीवन से जुड़े आवश्यक खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए ठोस और संवेदनशील कदम उठाएगी, ताकि महंगाई को हम से राहत मिल सके और जनजीवन संतुलित रह सके।

अरविंद रावल

कविता

<p>संजीव-नी</p> <p>सुकून का नन्हा सा द्वार।</p> <p>आशाएँ कभी शोर नहीं करतीं,</p> <p>वे धीरे से आंगन पर उतरती हैं</p> <p>धूप का एक छोटा सा बिम्ब</p> <p>कमरे में बिना ब कहे पसर जाता।</p> <p>उदासी का अपना एक पहलू,</p> <p>गहरी बिना चंद्र की निशा,</p> <p>उसी में कहीं बहुत हल्का सा उजाला</p> <p>शायद वही आशा है जो हार नहीं मानता।</p> <p>खुशियों के पल बहुत विशाल नहीं</p> <p>वे इतने छोटे होते अक्सर हमारे पास</p> <p>और हम उन्हें ढूंढते किसी दूर आकाश में।</p> <p>कभी एक मुस्कान</p>	<p>पूरी थकान उड़ा देती,</p> <p>एक शब्द</p> <p>मन के बर्फ को पिघलाते।</p> <p>तमस हटता नहीं</p> <p>एकबारगी</p> <p>वह थोड़ा-थोड़ा पीछे जाता ,</p> <p>जैसे कोई संकोची बच्चा भीड़ को दूर से निहारता।</p> <p>और तब</p> <p>हम महसूस करते</p> <p>जिंदगी उतनी उदास नहीं</p> <p>जितना हमने मान लिया ,</p> <p>उसमें कुछ उजाले पहले से</p> <p>आँखें बंद किए मौजूद हैं।</p> <p>आशाएँ</p> <p>दरअसल दरवाजा नहीं खोलतीं,</p> <p>वे बस इतना करती</p> <p>हमें याद दिलाती</p> <p>यह सुकून का नन्हा द्वार।</p>
---	--

संजीव तारु

स्वामी - स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचंद तहसील व जगदपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफस्टेड 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रिता। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तममे सम्मत समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। नोट: उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मे0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com



